डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जुलाई, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 जुलाई, 2021

| वर्ष 65 | अंक 4 | भोपाल | 16 जुलाई, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर "सहकारिता से बेहतर पुनर्निर्माण" कार्यक्रम संपन्न

सहकारिता में है पुनर्निर्माण की क्षमता - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 का शिलान्यास किया ● सहकारिता विभाग के विभागीय कार्य मैन्युअल का विमोचन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहाकरिता में अपार संभावनाएँ है। मैं के स्थान पर हम का भाव ही सहकारिता है। सब मिलकर काम करें और सबके भले में अपना भला का भाव सहकारिता ही है। कोरोना संक्रमण की चुनौती का प्रबंधन हो या लोगों के रोजगार और व्यापार को स्थापित करना हो, सहकारिता का सिद्धांत उद्धार का रास्ता दिखाता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी के कर कमलों से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित सहकारिता विभाग का "विभागीय कार्य मैन्युअल" का विमोचन किया गया। यह प्रथम अवसर है जब सहकारी विभाग का कोई कार्य मैन्युअल प्रकाशित हुआ है |

मुख्यमंत्री श्री चौहान अंतर्राष्ट्रीय समन्वय भवन में आयोजित सहकारिता दिवस के अवसर पर 'सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विपणन सहकारी संघ तथा आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण तथा 114 गोदामों का शिलान्यास डिजिटली किया। इन कार्यों की लागत लगभग 77 करोड़ 75 लाख रुपये है। इस अवसर पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल्ड स्टोरेज राऊ इंदौर, पैक्स बोरखेड़ा सीहोर, पैक्स लटेरी विदिशा और पैक्स बोरक्षार अलीराजपुर के सदस्यों से ऑनलाइन संवाद भी किया।

जबलपुर में 1904 में स्थापित हुआ सहकारी बैंक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। जबलपुर के सीहोरा में 1904 में सहकारी बैंक स्थापित हुआ। प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र मे सफलतम प्रयास हुए हैं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ खाद और बीच के लिए किसानों का सबसे बड़ा सहारा है। किसानों को शून्य-प्रतिशत पर कर्ज की सुविधा से बहुत राहत मिली है।

सहकारिता से संभव हुआ कोरोना नियंत्रण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण भी सहकारिता से ही संभव हुआ। प्रदेश में बना जन-भागीदारी मॉडल सहकारिता का ही रूप है। नगर से लेकर ग्राम और वार्ड स्तर तक बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने जिम्मेदारी संभाली। किसी भी काम के लिए सबके साथ आने से मिलने वाले परिणामों को पूरी दुनिया ने देखा। प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी सराहा है।

सांची ब्रांड ने बनाई पहचान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता में एक व्यक्ति की कोशिश कितना विशाल स्वरूप ले लेती है, यह डॉ. कुरियन द्वारा आरंभ-श्वेत क्रांति ने सिद्ध किया। आज अमूल जैसा संगठन पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। मध्यप्रदेश के सांची ब्रांड ने भी अपनी पहचान बनाई है। संतरों के लिए मालवा फ्रैश ब्रांड के साथ नीमच के लहसुन, बुरहानपुर के केले, अमरकंटक की गुल बकावली, डिण्डौरी की कोदो-कुटकी सहित प्रदेश की वनोपज और जड़ी-बूटियों में कई संभावनाएँ हैं।

सहकारिता आंदोलन से ही होगा आत्म-निर्भर भारत का निर्माण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारी आंदोलन से ही आत्म-निर्भर भारत का निर्माण होगा। सहकारिता में लोगों को जोड़ने और दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कोरोना काल की विपदा में सहकारिता बेहतर पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। परिवहन, मत्स्य उत्पादन, गृह निर्माण, ग्रामीण पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर गतिविधियों के संचालन से रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। इस संबंध में विषय विशेषज्ञों को जोड़कर नए विचारों पर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने चौहान ने सहकारिता से जुड़े अधिकारियों और प्रतिनिधियों से कहा कि आप नवाचार करें-इतिहास रचें मैं आपके साथ हूँ।

सहकारिता का गलत उपयोग न हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का गलत उपयोग न हो। निरंतर मॉनिटरिंग और सतर्कता आवश्यक है। सहाकरिता के सिद्धांत पर गठित गृह निर्माण समितियों में प्लाट हड़पने के कई प्रकरण सामने आएं हैं। अब तक 6 हजार प्लाट पात्र व्यक्तियों को वापस दिलाए जा चुके हैं। अन्य के संबंध में भी कार्यवाही जारी है। अत: सहकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उद्देश्य की स्पष्टता को बनाए रखना आवश्यक है।

सहकारिता में नवाचार आवश्यक - मंत्री डॉ. भदौरिया

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारिता हमारे देश और समाज की रग-रग मे बसी है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने उद्यानिकी, खनिज, श्रम और सहकारिता क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता बताई। डॉ. श्री भदौरिया ने जानकारी दी की अब सहकारी संस्थाओं का ऑन लाइन पंजीयन 45 दिन के अंदर हो रहा है। सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत होने वालों प्रकरणों की भी ऑन लाइन प्रक्रिया से सुनवाई की जा रही है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

नये सहकारिता मंत्रालय का गठन

नई दिल्ली। सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।

यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु–राज्य सहकारी समितियॉ(एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करता है।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने में राज्य सरकार से हर संभव मदद मिलेगी : श्री कुशवाह

खाद्य प्र-संस्करण व्यवसाय में संभावनाएँ विषय पर सेमीनार का हुआ आयोजन

भोपाल। मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) की अपार संभावनाएँ हैं और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रोजगार की सर्वाधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसे अपनाकर उद्यमी अपनी आय के साथ किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। साथ ही बेरोजगारों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के इच्छुक उद्यमियों को प्रदेश सरकार कच्चा माल, अनुदान और बाजार मुहैया करायेगी। यह बात प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने कही। श्री कुशवाह "खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय में संभावनाएँ" विषय पर आयोजित हुए सेमीनार में मौजूद उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में कैट (कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) और कृषि विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इक्यूवेशन एण्ड एंट्रोप्रेन्योरशिप कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में सेमीनार हुआ। ग्वालियर एवं चंबल अंचल के फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों ने सेमीनार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। साथ ही वर्चुअल रूप से प्रदेश के विभिन्न जिलों के उद्यमी इसमें शामिल हुए। सेमीनार की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. एस के राव ने की। इस अवसर पर कैट के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र जैन तथा सर्वश्री रवि गुप्ता, दीपक पमनानी व मनोज चौरसिया सहित कैट के अन्य पदाधिकारीगण तथा कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता एवं प्राध्यापकगण मौजूद थे।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कुशवाह ने कहा आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का है। इसलिए उद्यमी बेझिझक इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। प्रदेश सरकार फूड प्रोसेसिंग उद्यम स्थापित करने में कोई बाधा नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य उद्योग संवर्धन नीति के तहत उद्यमियों को बड़ी मदद देती है। सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुदान दे रही है। साथ ही उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के तहत भी कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए बड़ा अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार के बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से 2 करोड़ और उससे अधिक भी अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। उद्यमी सरकार के अनुदान के आधार पर 5 हजार मैट्रिक टन और उससे बड़े कोल्ड स्टोर भी खोल सकते है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 10 हजार 500 छोटी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने जा रही है, जिससे प्रदेश के 85 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्री कुशवाह ने जानकारी दी कि कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा सभी 52 जिलों के लिए "एक जिला – एक उत्पाद" कार्यक्रम लागू किया गया है।

श्री कुशवाह ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से अनुदान प्राप्त कर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सर्वाधिक आवेदन मध्यप्रदेश के उद्यमियों ने प्रस्तुत किए हैं। जल्द ही इनका निराकरण होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में दिक्कत होने पर विभाग के मंत्रालय अथवा उनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस के राव ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ने उद्यमियों एवं किसानों को एंट्रोप्रेन्योर बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग से सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इक्यूवेशन एण्ड एंट्रोप्रेन्योरशिप कंपनी का गठन कर बेहतर प्लेटफार्म मुहैया कराया है। इसके लिए लगभग 60 से 70 आर्थिक गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में यह कंपनी बनने से निश्चित तौर पर ग्वालियर-चंबल अंचल के किसानों एवं उद्यमियों को विशेष फायदा पहुँचेगा।

कार्यक्रम में सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इक्यूवेशन एण्ड एंट्रोप्रेन्योरशिप कंपनी द्वारा अंजाम दी जाने वाली गतिविधियों और एंन्ट्रोप्रेन्योर से संबंधित बारीकियों पर प्रजेण्टेशन के जरिए विस्तार से प्रकाश डाला गया।

उद्यमियों के अच्छे सुझावों पर होगा अमल

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने सेमीनार में उद्यमियों के सुझाव व समस्याएँ सुनीं। उन्होंने कहा अच्छे सुझावों पर विभाग द्वारा अमल किया जाएगा। श्री कुशवाह ने कैट के सहयोग से प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे सेमीनार आयोजित करने की बात भी इस अवसर पर कही।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंदौर में निर्माणाधीन पी.एम. आवास योजना के लाइट हाउस प्रोजेक्ट को वर्चुअली देखा

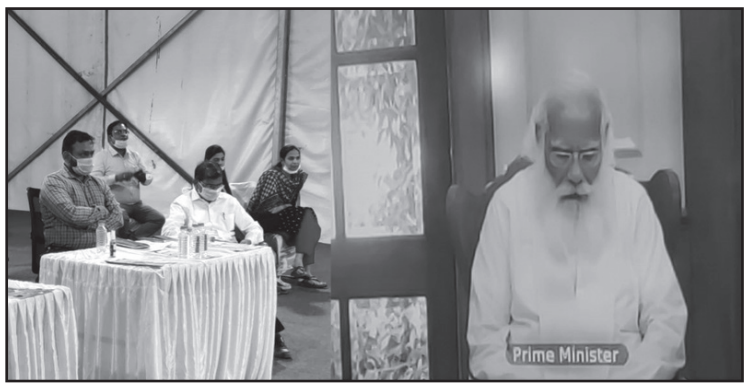

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा ने इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये जा रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को नई दिल्ली से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी देते हुए ड्रोन के माध्यम से निर्माण स्थल की वस्तुस्थिति से अवगत भी करवाया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा एक जनवरी 2021 को देश के 6 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया था। इसी क्रम में इंदौर कनाडिया एक्सटेंशन के आगे गुलमर्ग परिसर में 128 करोड़ रूप की लागत से 1024 इकाइयों का सैंडविच पैनल के माध्यम से निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के स्थल पर आयुक्त नगर निगम सुश्री प्रतिभा पाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन डायरेक्टर श्री रोहित सिंह, अपर आयुक्त श्री रजनीश कसेरा, कार्यपालन यंत्री श्री महेश शर्मा आदि उपस्थित थे।

दिव्यांगजनों को पहचान-पत्र देने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश दिव्यांगजनों को पहचान-पत्र (यूडीआईडी) देने में देश में शीर्ष स्थान पर है । केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित 6 लाख 7 हजार 313 लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में अब तक 5 लाख 97 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को पहचान-पत्र जारी किये जा चुके हैं। ट्रांसजेंडर को पहचान-पत्र देने में भी मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। देश में सर्वप्रथम 8 जनवरी, 2021 को भोपाल कलेक्टर द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

श्री पटेल ने यह बात अपने प्रभार जिले बुरहानपुर में प्रथम प्रवास के दौरान 3 दिव्यांगजन को परिचय एवं प्रमाण-पत्र, 4 नव-विवाहित जोड़ों को नि:शक्त विवाह प्रमाण-पत्र और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग कुमारी हर्षाली को लेपटॉप और आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए कही। श्री पटेल ने मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में प्रत्येक जोड़े को 2-2 लाख रूपये की राशि प्रदान की। विधायक श्रीमती सुमित्रा कास्डेकर और पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस भी मौके पर उपस्थित थीं। श्री पटेल ने विभागीय और हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर प्रबंधन के परिणाम स्वरूप आज बुरहानपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या शून्य है। पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने आज बुरहानपुर जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिये की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्टॉफ से चर्चा भी की। चिकित्सालय में बच्चों के लिये 10 बेड गहन चिकित्सा इकाई, बच्चों के लिये वेंटीलेटर, बाईपेप, आईसीयू वार्ड, सीटी स्केन, सोनोग्राफी, सर्जिकल वार्ड, कोविड के उपचार के लिये पर्याप्त दवाइयाँ और उपकरण आदि की विस्तृत जानकारी ली।

गरीबों के लिये सरकार की सबसे अधिक जवाबदारी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मध्यप्रदेश को लोक कल्याणकारी राज्य के मॉडल के रूप में स्थापित करना है ● मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गरीब कल्याण पर गठित मंत्री समूह को संबोधित किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की सबसे अधिक जवाबदारी गरीबों के प्रति है। गरीब और वंचित वर्ग को ही सरकार के सहयोग और समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश को लोक कल्याणकारी राज्य के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। अत: गरीब और वंचित वर्ग की तात्कालिक सहायता वाली योजनाओं के साथ उनके स्थाई सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए हरसंभव प्रयास पूरी गंभीरता से किए जाएँ। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के साथ स्थाई आजीविका के लिए बहुआयामी गतिविधियाँ संचालित की जाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप के अंतर्गत गरीब कल्याण के लिए गठित मंत्री-समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पशुपालन, सामाजिक न्याय तथा नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और समूह समन्वयक प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया।

योजनाओं के फीडबैक के लिए हितग्राहियों से जीवंत संवाद आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्यान्न वितरण का दायित्व स्व-सहायता समूहों को सौंपने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही गरीबों को तत्काल लाभ देने वाली वनोपज आधारित गतिविधियों और बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसी पशुपालन से संबंधित, हितग्राहीमूलक योजनाओं का व्यापक रूप से संचालन भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री सहित सभी जन-प्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से जीवंत संवाद रखें। इससे योजनाओं के संबंध में आवश्यक फीडबैक मिलेगा और उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

गरीबों के खाद्यान्न से छेड़छाड़ न हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्यान्न वितरण संवदेनशील योजना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों की मॉनीटरिंग क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा कराई जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कालाबाजारी की धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। गरीबों के लिए दिए जा रहे खाद्यान्न से छेड़छाड़ पर कलेक्टर और एसडीएम नजर रखें। तहसील और विकासखण्ड स्तर पर भी सतर्कता बनाए रखी जाए।

खाद्यान्न वितरण की नवीन श्रेणी में ट्रांसजेंडर्स भी शामिल

बैठक में जानकारी दी गई कि खाद्यान्न वितरण के अंतर्गत नवीन श्रेणी में घरेलू कामकाजी कर्मी, ट्रांसजेंडर्स, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सम्मिलित परिवारों और अन्य वंचित वर्ग को जोड़ा गया है। प्रदेश में 24 हजार 500 दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है। 'वन नेशन वन राशन' के अंतर्गत लगभग 4 लाख परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन वितरण किया गया है।

3 लाख 16 हजार पथ-विक्रेताओं को 316 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण

बैठक में जानकारी दी गई कि शहरी गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत 119 रात्रिकालीन आश्रय स्थलों का नवीनीकरण किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का विस्तार 407 शहरों तक कर लिया गया है। प्रदेश में 3 लाख 16 हजार पथ-विक्रेताओं को 316 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत 5,416 स्व-सहायता समूहों का गठन कर 54 हजार 160 परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। प्रदेश में 27 हजार 452 युवाओं को कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

महिला स्व-सहायता समूह करेंगे सड़कों का संधारण

बैठक में बताया गया कि जनजाति बाहुल्य 15 जिलों में सड़कों का संधारण महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में कृषि एवं किसान-कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को जिलों का प्रभार आवंटित

भोपाल : राज्य शासन ने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को जिलों के प्रभार सौंप दिये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

गृह, जेल, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को इंदौर, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव को जबलपुर, निवाड़ी, जल-संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर, हरदा, वन मंत्री कुँवर विजय शाह को सतना, नरसिंहपुर, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा को उज्जैन, कटनी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह को मण्डला, रीवा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को देवास, आगर-मालवा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह को भोपाल, जनजातीय कार्य, अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे को सीधी, अनूपपुर, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल को खरगोन, छिंदवाड़ा, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत को भिण्ड, दमोह, खनिज साधन तथा श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह को होशंगाबाद, सिंगरौली, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग को टीकमगढ़, विदिशा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी को धार, सीहोर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया को शिवपुरी, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अशोकनगर, गुना, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल को बुरहानपुर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा को छतरपुर, सिवनी, पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर को नीमच, खण्डवा, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया को सागर, रायसेन, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव को राजगढ़, डिण्डोरी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग को बड़वानी, बालाघाट, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मंदसौर, अलीराजपुर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह को मुरैना, श्योपुर, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार को बैतूल, झाबुआ, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल को शहडोल, आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल-संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे को उमरिया, पन्ना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव को शाजापुर, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़ को दतिया और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया को रतलाम जिले का प्रभार सौंपा गया है।

वैज्ञानिक आर्थिक विकास और समाज उपयोगी प्रोजेक्ट पर काम करें-मंत्री श्री सखलेचा

वैज्ञानिक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें, जिसका उपयोग प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास मे प्रभावी हो। यह निर्देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की विभिन्न साइंस प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक में दिए।

मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि प्रोजेक्ट को इस तरह तैयार करना चाहिये कि उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे और उसका लाभ ग्रामीणों का जीवन बेहतर बनाने में किया जा सके। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को अपनी पचास प्रतिशत ऊर्जा युवा वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रेरित करने और शेष आधी ऊर्जा समाज के आर्थिक विकास के लिए करना चाहिये।

समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव श्री एम. सेलवेन्द्रन ने सिलसिलेवार ऑन-गोइंग प्रोजेक्टस के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक परियोजनाओं को बनाते समय उसकी भावी संभावनाओं, उद्देश्यों और प्रभावों पर भी गौर करना चाहिये। श्री सेलवेन्द्रन ने कहा कि प्रोजेक्ट समयबद्ध और परिणाममूलक होना चाहिये।

परिषद के महानिदेशक डॉ.अनिल कोठारी ने बताया कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक शहरी विकास से लेकर बायोटैक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर से पैदा होने वाले मेडिसिनल प्लांट्स से लेकर जल संसाधनों से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम कर रहे है।

शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एमआईएस सिस्टम और हेल्प डेस्क कारगर साबित होगी : स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

भोपाल। प्रदेश के नागरिकों को मिलावट रहित शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में एमआईएस सिस्टम और हेल्प डेस्क को खाद्य प्रशासन विभाग द्वारा शुरू करना महत्वपूर्ण पहल है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के ईदगाह हिल्स स्थित कार्यालय में एमआईएस सिस्टम और हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि हेल्प डेस्क के माध्यम से एक ओर जहाँ विभागीय गतिविधियों, योजनाओं की जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक अपनी बात भी विभाग तक पहुँचा सकेगा। एमआईएस सिस्टम के माध्यम से विभाग के कार्य में कसावट आएगी। जिलावार और अधिकारीवार कार्यों को सीधे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे विभागीय कार्यों की निगरानी, नियंत्रण और समीक्षा के माध्यम से विभागीय कार्यों में तेजी लायी जायेगी। कौन अधिकारी कितने सेम्पल कलेक्ट कर रहा है, किस जिले से कितने सेंपल कलेक्ट हुए आदि की विस्तृत जानकारी इसमें होगी। एमआईएस सिस्टम मेन्यूअल सर्विलेंस सेम्पल एवं चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जाँच हेतु लिये जाने वाले खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूनों की संख्यात्मक जानकारी को भी पोर्टल पर दर्ज करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में की जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को भी एमआईएस सिस्टम में सम्मिलित किया गया है। जिला स्तर पर एमआईएस सिस्टम में डाटा एंट्री मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दर्ज की जायेगी। दर्ज सभी प्रकार की जानकारी का डाटा डेशबोर्ड पर पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट के रूप में रहेगा, जो प्रभावी मॉनिटरिंग में सहायक होगा। इस डेटा को पोर्टल पर संभागवार/जिलावार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी वार प्रथक-प्रथक दर्शाया जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने शिकायत एप के संबंध में बताया कि यह एक वेब आधारित एप है, जिस पर वेबसाइट के माध्यम से कोई भी आम नागरिक अपनी पहचान बताये बिना किसी खाद्य पदार्थ के दूषित होने, मिलावटी खाद्य पदार्थ संबंधी शिकायत अथवा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के पालन नहीं होने की अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज होने पर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पंजीकृत ई-मेल पर एमआईएस सिस्टम के द्वारा कार्यवाही के लिये नोटिफिकेशन भेजा जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध चलाये गये मिलावट से मुक्ति अभियान में अब तक 11 हजार 638 नमूनों की जाँच की गई। मिलावट पाये जाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 288 मिलावटखोरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें 32 के लिए एनएसए की कार्यवाही की गई। अब तक मिलावटखोरों से 2 करोड़ 3 लाख 97 हजार का अर्थदंण भी वसूल किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि विभागीय प्रयासों से राज्य प्रयोगशाला की जाँच क्षमता 500 सेंपल प्रतिमाह से बढ़ाकर 1700 सेंपल प्रतिमाह की गई है। औषधि प्रयोगशाला की जाँच क्षमता को भी 200 सेंपल से बढ़ाकर 450 सेंपल प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा कि सेंपल की विश्लेषण क्षमता बढाने के लिये इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 3 नई प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन प्रयोगशालाओं को इस वर्ष के अंत तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि आम नागरिकों को खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के संबंध में जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिये विभाग द्वारा 9 चलित खाद्य प्रयोगशाला जिलों में संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को जल्दी ही 3 नई चलित प्रयोगशाला मिलने वाली हैं। चलित प्रयोगशाला में आम नागरिक खाद्य पदार्थों की जाँच नाम मात्र की 10 रूपये की शुल्क देकर करा सकते हैं।

एमआईएस सिस्टम और हेल्प डेस्क शुभारंभ कार्यक्रम में स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी और नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री पी. नरहरि ने एमआईएस सिस्टम और हेल्प डेस्क के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

एनबीएच का केन्द्र किसानों के लिए वरदान साबित होगा : श्री तोमर

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केन्द्र का उद्घाटन व मुरैना में शहद गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का भूमिपूजन हुआ

नई दिल्ली/ग्वालियर। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनबीएच), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की गतिविधियों व कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में (एन.एच.बी.) के केन्द्र का उद्घाटन किया। यह ग्वालियर अंचल को बड़ी सौगात है, जिसके माध्यम से उत्तरी म.प्र. के 21 जिलों के किसान लाभन्वित होंगे। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि यह केंद्र समूचे क्षेत्र के किसानों के जीवन में वरदान साबित होगा। किसान इस केन्द्र का लाभ उठाएं व अपने जीवन को उन्नत बनाएं। उन्होंने कहा– कृषि क्षेत्र व किसानों के विशेष फायदे के लिए केंद्र सरकार ने चौतरफा उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण देश हर क्षेत्र में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि म.प्र. में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए यह नया केंद्र इस क्षेत्र में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, ग्वालियर अंचल में भी ये केंद्र विकास के मायने में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। नया केंद्र ग्वालियर में खुलने से न केवल ग्वालियर संभाग के किसान, बल्कि उत्तरी मध्यप्रदेश के 21 जिलों के किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) की योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इस केन्द्र से जिन 21 जिलों को कवर किया जाएगा, उनमें चंबल, ग्वालियर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिले शामिल हैं। ये जिले हैं– ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, अशोक नगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवारी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। ग्वालियर–चंबल क्षेत्र सहित इन 21 जिलों के बागवानी से जुड़े किसानों को अब भोपाल या दिल्ली जाने–आने की दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी, उनके सारे काम अब ग्वालियर केंद्र में ही संपन्न हो जाएंगे। श्री तोमर ने यह केन्द्र प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय व एन.एच.बी. के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

हनी हब बनेगा चंबल क्षेत्र

श्री तोमर ने कहा कि इसी तरह से ग्वालियर–चंबल क्षेत्र में एक के बाद एक विकास के कार्य प्रारंभ किए जा रहे है। शीघ्र ही चंबल क्षेत्र देश में हनी हब के रूप में स्थापित होगा, जिसके लिए मुरैना जिले में नेफेड द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत, शहद एवं मधुमक्खीपालन के अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला–इकाई का भूमि पूजन किया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि शहद उत्पादन में म.प्र. में मुरैना अग्रणी है। यहां लगभग 6 हजार मधुमक्खी पालक व 1 लाख मधुमक्खियों के बक्सों की संख्या है, जिससे 3 हजार टन शहद उत्पादन होता है। नेफेड के जरिये केंद्र सरकार ने एक एफ.पी.ओ. यहां बनाया है। कृषि अनुसंधान केन्द्र मुरैना में समन्वित मधुमक्खीपालन केंद्र हैं जो ट्रेनिंग देकर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित हनी बी एवं पालीनेटर केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मुरैना क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पर स्थापित होने से यहां मधुमक्खी पालन पर नवीन अनुसंधान का लाभ मधुमक्खी पालकों को मिल सकेगा। मीठी क्रांति को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेने के लिए श्री तोमर ने नेफेड को बधाई व शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में, म.प्र. के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारतसिंह कुशवाहा एवं ग्वालियर सांसद श्री विवके नारायण शेजवलकर ने ग्वालियर अंचल को एनएचबी के केंद्रों की सौगात देने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर को धन्यवाद दिया। नेफेड के एमडी श्री संजीव चड्ढा व एनएचबी के एमडी श्री राजबीर सिंह भी मौजूद थे, वहीं केन्द्रीय कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी वर्चुअल जुड़े हुए थे।

हितग्राहियों को थैले में दिया जाएगा नि:शुल्क उचित मूल्य राशन

प्रदेश के 4 करोड़ 81 लाख व्यक्ति होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संबंधी बैठक ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से आगामी नवम्बर माह तक प्रदेश के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार एक रूपए किलो उचित मूल्य राशन भी प्रदान करेगी। हितग्राही परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो नि:शुल्क राशन और 5 किलो राशन एक रूपए किलो के मूल्य पर मिलेगा। यह राशन हितग्राहियों को 10 किलो के थैले में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के 4 करोड़ 81 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। उन्होंने योजना के समुचित क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी आदि उपस्थित थे।

हर माह प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान्न

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न गेहूँ/चावल एक रूपए किलो में प्रदान किए जाते हैं। साथ ही एक किलो नमक और एक किलो उचित मूल्य शक्कर भी दी जाती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवम्बर तक प्रति सदस्य 5 किलो नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार नवम्बर तक हर माह प्रति सदस्य 10 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा।

25 हजार उचित मूल्य दुकानें, एक करोड़ 13 लाख पात्र परिवार

प्रदेश में कुल 25 हजार 423 उचित मूल्य दुकानें हैं, एक करोड़ 13 लाख पात्र परिवार हैं और 4 करोड़ 81 लाख हितग्राही हैं। खाद्यान्न का मासिक आवंटन 2 लाख 62 हजार मीट्रिक टन, शक्कर का मासिक आवंटन 1450 मी.टन और नमक का मासिक आवंटन 11 हजार 326 मी.टन है।

अन्न महोत्सव आयोजित होगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शीघ्र ही प्रदेश की हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दिन हितग्राहियों को समारोहपूर्वक थैले में रखकर नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालन को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना जिला सिंगरौली में संचालित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाईड करनेल मिलाकर वितरित किया जाएगा। हितग्राहियों को चावल का प्रदाय एक रूपए प्रति किलो की दर से किया जाएगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014

मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 को राज्य शासन के विभागों एवं उपक्रमों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू करने का निर्णय लिया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण/रेलवे की परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना, निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर, भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से, प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सके तथा शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" 14 नवम्बर 2014 से लागू है।

उपरोक्त नीति, वर्तमान में, केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों के मामले में लागू नहीं है। केन्द्र सरकार के कई विभागों/उपक्रमों द्वारा इस नीति में उन्हें भी शामिल करने की मांग की जाती है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रेलवे मुख्य है।

इंदौर को मिली ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक की सौगात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर को एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक (एचएसटी) की सौगत मिली है। इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, के प्रति आभार व्यक्त किया । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत देश को ऑटो हब बनाने के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देगा। साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एनएटीआरएएक्स को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। जहाँ पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे, जो कि वाहनों के लिए सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा।

एनएटीआरएएक्स केंद्र

एनएटीआरएएक्स केंद्र में कई परीक्षण क्षमताएँ हैं जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन, तय गति पर ईंधन की खपत क्षमता, रियलरोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन बदलने के दौरान के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की सुविधा है।इसके अलावा यह वाहनों के डायनेमिक्स का एक उत्कृष्टता केंद्र है।

एचएसटी का इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसी हाई-एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जिसे किसी अन्य भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है। मध्यप्रदेश में स्थित होने के कारण, यह अधिकांश ओईएम के लिए सुलभ है। यह सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जो दुनिया में सबसे बड़े ट्रैकों में से एक है। यह सभी तरह की श्रेणी वाले वाहनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। दो पहिया वाहनों से लेकर सबसे भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के वाहनों का इस ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। ट्रैक के घुमावों पर वाहनों की स्टेयरिंग का नियंत्रण 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर भी किया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक को कम अंडाकार बनाया गया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित परीक्षण ट्रैक में से एक बनाता है।

बाजार मूल्य गाइडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी

भोपाल। राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन की अवधि 30 जून से बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिध्दांतों के पुनरीक्षण नियम 2018 के नियम-12 में प्रदत्त शक्तियों के अर्तगत 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाईन की समयावधि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई है।

लघु-सीमांत किसानों का फसल बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी : श्री पटेल

भोपाल। म.प्र. में खरीफ फसलों की बुवाई लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 50 फीसदी कर ली गई है। वहीं किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि किसानों के साथ धोखाधडी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाई करें। इसके साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए उनका प्रीमियम सरकार भरेगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग योजना तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों का फसल बीमा प्रीमियम सरकार जमा करेगी।

श्री पटेल ने बताया कि राज्य में अब तक खरीफ फसलों की बोनी 75 लाख हेक्टेयर में कर ली गई, जो लक्ष्य 149.29 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 50.2 फीसदी है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बुआई 36.83 लाख हे. में एवं धान की बोनी 9.63 लाख हे. में कर ली गई। उन्होंने बताया कि अन्य प्रमुख फसलों के तहत मक्का 12.58 लाख हे. में, अरहर 1.88 लाख हे., उडद 5.93 लाख हे. एवं कपास 5.04 लाख हे. में बोई गई है।

कृषि आदानों जैसे खाद, बीज एवं कीटनाशकों के संबंध में कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों को गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संकल्प लिया है जिससे किसान धोखाधडी से बच सके एवं उत्पादन बेहतर हो। उन्होंने

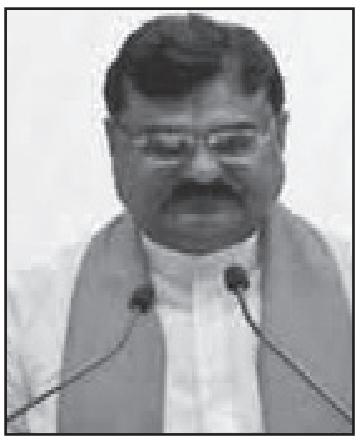

बताया कि इसके लिए कृषि अधिकारियों को अधिक से अधिक सम्पलिंग करने के निर्देश दिए गए है तथा अमानक एवं नकली आदान पाए जाने पर विक्रेता का लायसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में बडी संख्या में किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) बनाऐ जा रहे है, जिससे किसान अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित कर लाभ अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चाक–चौबंद व्यवस्था की गई है। रैकों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए है।

श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भर म.प्र. रोडमैप 2023 तैयार किया जा रहा है जिसमें मिट्टी को केन्द्र में रखकर संसाधनों को नियोजित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

कृषि मंत्री ने जताया आभार :

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कृषि और कृषि अवसंरचना फंड में एक लाख करोड रूपये के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है । उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक लाख करोड की कृषि अधोसंरचना निधि मंडियों के माध्यम से विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं में खर्च होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में म.प्र. पूरे देश में अग्रणी

भोपाल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश को देश में प्रथम आने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मजदूरी में लगी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दिलाने और गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नगद राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित है। योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश लगातार तीसरी बार देश में प्रथम आया है। पहले बच्चे के जन्म पर 5 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत 21 जून 2021 तक प्रदेश में 23 लाख 7 हजार 880 गर्भवती महिलाओं को 991 करोड़ 89 लाख रूपये का भुगतान किया गया। योजना में प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूध 148 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को बधाई दी है। द्वितीय रहे हिमाचल प्रदेश में 139 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। तृतीय रहे आंध्रप्रदेश में 11 लाख 69 हजार 730 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। योजना में मध्यप्रदेश पिछले तीन वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

तीन किश्तों में दी जाती है सहायता

योजना में पहले बच्चे के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हजार रूपये की सहायता तीन किश्तों में दी जाती है। एक हजार रूपये की पहली किश्त आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का पंजीयन कराने पर, दो हजार रूपये की दूसरी किश्त कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने और गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर तथा दो हजार रूपये की तीसरी किश्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण और बच्चे के प्रथम चक्र के टीकाकरण पूर्ण होने पर दी जाती है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता में है पुनर्निर्माण की क्षमता....

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वीकृत किया भवन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आलू भंडारण में सक्रिय कोल्ड स्टोरेज राऊ के श्री रामनारायण, पैक्स बोरखेड़ा नसरूल्लागंज सीहोर के श्री कैलाश पवार से खाद्यन्न वितरण, पैक्स लटेरी विदिशा के श्री मुकेश शर्मा से निर्माण कार्य और अलीराजपुर के श्री डुईला से उनकी संस्थाओं के सदस्यों के संबंध में बातचीत की। पैक्स बोरखेड़ा नसरूल्लागंज के प्रतिनिधियों ने निम्ना गाँव में खाद्यन्न भंडारण के लिए भवन की मांग की। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भवन के लिए तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई।

सहकारिता और भंडार निगम बनाएगा गोदाम

अनाज भंडारण क्षमता 50 लाख मीट्रिक टन करने की तैयारी

भोपाल। सरकार प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के संबंध में रोडमैप तैयार कर रही है। प्रदेश में करीब 50 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण के हिसाब से गोदाम बनाए जाएंगे। भंडार निगम व सहकारिता विभाग समितियों के माध्यम से गोदामों का निर्माण कराएगा।

प्रदेश में मौजूदा समय में 50 लाख मीट्रिक टन गोदामों की कमी है। करीब 30 लाख मीट्रिक टन गेंहू खुले कैप में रखा है। सरकार अब इन खुले कैपों को बंद गोदामों में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार कैप बनाने करोड़ों रूपए हर साल खर्च करती है। बंद गोदामों में एक बार पैसे लगाने के बाद रख–रखाव के अलावा कोई राशि नहीं खर्च करनी पड़ती है। कई जिलों में सहकारिता विभाग और भंडार निगम आत्मनिर्भर भारत योजना के तरह गोदाम बना रहा है। इसमें गोदामों के निर्माण की लागत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। समितियों को भंडारण के लिए जॉब गारंटी भी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 60 फीसदी निजी गोदामों में अनाज का भंडारण किया गया है।

इन गोदाम संचालकों को 5 माह की जॉब गारंटी भी दी जा रही है। भारतीय खाद्य निगम ने भी निजी गोदामों को किराए पर ले रखा है।

जल जीवन मिशन में 39 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पहुँचा नल से जल

भोपाल। प्रदेश में जल जीवन मिशन में अब तक 39 लाख एक हजार 181 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। समूची ग्रामीण आबादी के लिए एक करोड़ 3 लाख नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में आईएमआईएस पोर्टल पर दर्ज करीब 95 हजार शालाओं और 66 हजार से अधिक आँगनबाड़ियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये नल कनेक्शन दिए जाने का कार्य प्रगतिरत है। अब-तक स्कूल तथा आँगनबाड़ियों में 26 हजार से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिये गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के अनुरूप जल जीवन मिशन के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

स्वयं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन की समय-समय पर समीक्षा की है। ग्रामीण अंचल में माता-बहनों को नदी, कुँआ, तालाब, बावड़ी तक जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़े, इस उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को गति देकर ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिये पानी उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है। कोविड-19 के कारण समूचे विश्व की तरह प्रदेश भी प्रभावित हुआ। मिशन के कार्य मानव तथा अन्य संसाधनों के अभाव में करीब सवा वर्ष तक गतिशून्य से रहे हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही जल जीवन मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के 2985 ग्रामों की शत-प्रतिशत आबादी को नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा चुकी है।

मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष वित्त पोषण योजना में किया संशोधन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंचना कोष के तहत वित्तपोषण सुविधा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संशोधनों की जानकारी देते हुए बताया, अब पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों/एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों (एफपीओ) तथा स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों तक किया गया है।

योजना के तहत वर्तमान में एक स्थान पर 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्रता है। यदि एक पात्र इकाई विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजना 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्र होंगी। लेकिन निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महांसघों पर लागू नहीं होगी।

स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। श्री तोमर ने बताया इसी के साथ एपीएमसी के लिए एक बाजार यार्ड के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों जैसे कोल्ड स्टोरेज, सार्टिंग, ग्रेडिंग ओर परख इकाइयों , साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में लाभार्थी को जोड़ने या हटाने के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कृषि मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना परिवर्तन न हो। इस वित्तपोषण योजना की अवधि 2025–26 तक 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है ओर 2032–33 तक इस योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है।

हाईटेक बागवानी से अधिक आय और कृषक उद्यमिता का विकास

सब्जियों की खेती से फायदा लेने के लिए बेमौसमी खेती ही एक मात्र विकल्प है। सब्जियों की खेती विशिष्ट मौसम में की जा सकती है। जो सब्जियों ग्रीष्म ऋतु की होती है, उन्हें मार्च से सितम्बर तक उगाया जा सकता है एवं शीत ऋतु की सब्जियां अक्टूबर से फरवरी तक उगायी जा सकती है। ऐसे में इन सब्जियों की भरपूर पैदावार होने के बावजूद भी किसान को यथोचित लाभ नहीं मिल पाता है। बेमौसम में इन सब्जियों की खेती सामान्य रूप से नहीं की जा सकती है, क्योंकि तापमान एवं जलवायवीय कारक अनुकूल नहीं होते एवं वांछित पैदावार नहीं मिल पाती है।

हाइटेक बागवानी के नये एवं आधुनिक आयामों से सब्जियों की बेमौसमी खेती करके अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ सब्जियों की कीमत भी अच्छी मिल जाती है। हाइटेक बागवानी के अन्तर्गत पॉलीहाउस, छाया–गृह, लौट–नल, नेट–हाउस एवं वाकिंग टनल इत्यादित कुछ ऐसे विकल्प है, जिसमें मुख्य मौसम से परे सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इन संरचनाओं से तापमान और आर्द्रता को नियंत्रण करके पौधों को उनके अनुकूल वातावरण दिया जाता है, जिससे पौधे अपने मुख्य मौसम की तरह वृद्धि और विकास करते है। इस तरह से संरक्षित वातावरण में खेती से पैदावार तथा गुणवत्ता कई गुना बढाई जा सकती है। इसके अलावा बागवानी उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना में बढ जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एक क्रांति के रूप में बागवानी विकास अथवा उद्यमिता विकास किया जा रहा है, नई नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है तथा इसके लिए वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है। आजकल बागवानी के क्षेत्र में विकसित कुछ तकनीक जैसे– प्लान्ट टिशू कल्चर, खेती सद्यन प्रणाली, मृदा विहीन खेती (हाइड्रोपोनिक) तथा पॉलीहाउस प्रणाली उद्यानिकी की प्रमुख उच्च प्रौद्योगिकी है। इन सभी तकनीक से बागवानी क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है।

1. ऊतक संवर्धन :–

पदप टिशू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कोशिका, ऊतक, अंगो और यहां तक कि पूरे पौधे को अपनी इच्छानुसार पूरे साल मौसम संबंधी सीमाओं से परे, प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है। इस तकनीक से कम रोगयुक्त तथा उत्तम गुणवत्ता के पौधों की बढती मांग ने टिशू कल्चर और सूक्ष्म प्रजनन के क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाओं को चार चांद लगा दिये है। इस विधि द्वारा तैयार पौधों की निर्यात की भी अच्छी क्षमता है।

2. सघन पौध रोपण प्रणाली :– सघन पौधरोपण प्रणाली से यह तात्पर्य है, जिसमें एक या एक से अधिक फसलें प्रति इकाई क्षेत्र में परम्परागत विधि से अधिक पौधरोपण कर भूमि, प्रकाश, पानी व पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। इस पौध रोपण प्रणाली में फल वृक्षों की संख्या 500 से 100000 हो सकती है।

पौध रोपण प्रति हेक्टयर के आधार पर इसे निम्न समूह में विभाजित किया जा सकता है–

1. मध्यम सघन पौध रोपण 500–1500 पौध प्रति हेक्टयर
2. ईष्टतम सघन पौध रोपण 1500–10000 पौध प्रति हेक्टयर
3. अति सघन पौध रोपण 10000–100000 पौध प्रति हेक्टयर

सघन बागवानी से लाभ :–

1. पारम्परिक पौध रोपण (150–200 पौध प्रति हेक्टयर) की जगह सघन बागवानी में 500 से 1 लाख पौधे प्रति हेक्टर प्रति इकाई क्षेत्र में लगा सकते है, जिससे जहां उत्पादकता 15 से 20 टन प्रति हेक्टर होती थी वहीं सघन रोपण से 30 से 50 टन प्रति हेक्टर होती है।
2. पारम्परिक विधि में प्रति पौधा आकार ज्यादा बडा होने से सूर्य का प्रकाश हर भाग में पहुंचाना आसान नहीं होता, वहीं सघन रोपण में उचित कटाई–छंटाई अपनाने से पौधें के हर हिस्से को सूर्य का उचित प्रकाश मिलता है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली आदर्श उपज प्राप्त होती है।
3. पारम्परिक विधि में फलों की तुडाई हाथ से करने पर समय व लागत अधिक आती है वहीं सघन प्रणाली में मशीनों द्वारा कम समय व लागत में तुडाई हो जाती है।
4. पारम्परिक विधि से बाग की व्यवसायिक उपज 7–8 साल पर आती है जबकि सघन रोपण में 5–6 साल पर उपज आ जाती है।

3. ग्रीन हाऊस तकनीक

ग्रीन हाऊस तकनीक, उच्च उत्पादकता के आधार पर कम क्षेत्र से अधिक उत्पादन उपलब्ध करने में सक्षम है। पॉली हाऊस में सब्जियों में प्रमुखतया खीरा, विभिन्न प्रकार की शिमला मिर्च एवं टमाटर की खेती लाभप्रद है जबकि फूलों में जरबेरा, कोर्नेशन एवं गुलाब अत्याधिक लाभप्रद सिद्ध हुए है।

पॉली हाऊस के भीतर वातावरण बाहर के वातावरण से भिन्न रहता है। बिना किसी नियंत्रण के प्रणाली वाले पॉली हाऊस के अन्दर का तापमान बाहरी तापमान से 5–10 डिग्री से ज्यादा रहता है, जबकि पूर्ण रूप से नियंत्रण वाले पॉली हाऊस में तापमान, नमी, प्रकाश आदि फसल की आवश्यकतानुसार निर्धारित किए जाते है। ऐसे हरित गृह का खर्चा अधिक तथा रखरखाव भी कठिन होता है। परन्तु इनमें मनचाही फसल किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। पॉली हाऊय तकनीक से प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन (4–5 गुना) अधिक मिलता है। साथ ही बेमौसमी फल सब्जियॉ और फूलों की कीमत भी अच्छी मिलती है। इस तकनीक से प्राप्त उत्पादन की गुणवत्ता उच्च कोटि की होती है। इस पद्धति को अपनाकर शिक्षित युवा रोजगार प्राप्त कर अच्छा धन अर्जित कर सकते है। किसानों को ग्रीन हाऊसों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का फायदा उठाकर ग्रीन हाऊसों में बैमौसमी सब्जी का उत्पादन करके संरक्षित की जा सकती है।

सहकारिता को क्षेत्रीय विकास का वाहक बनाएगा नवगठित मंत्रालय

सहकार से समृद्धि : गांव, गरीब, किसान, बुनकर, मछुआरे व उपभोक्ता होंगे सशक्त

नई दिल्ली, ब्यूरों : केन्द्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की तर्ज पर सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने को एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। निचले स्तर के सहकार सदस्य किसान, बुनकर, मछुआरे और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में सरकार का यह फैसला अहम साबित होगा।

नवगठित सहकारिता मंत्रालय के दायरे में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण के साथ सहकारिता संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। कृषि मंत्रालय के अधीन चल रहे सहकारिता क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वर्तमान में कोई संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तक नियुक्त नहीं है, जबकि देश में आठ सहकारी संस्थाओं के 40 करोड़ सदस्य हैं। राज्यों में अलग–अलग कानून और नियमों के चलते सहकारिता आंदोलन अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा है।

नेशनल को–ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के प्रेसिडेंट दिलीप संघानी का कहना है कि इससे सहकारिता नई उंचाई हासिल करेगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 14,000 से अधिक सहकारी बैंकों की शाखाएं काम कर रही है, जो स्थानीय ग्राहकों की जरूरतें पूरी करती है। सहकारी बैंकों की अनियमितताओं को दूर करने के लिए आरबीआई ने पहले ही रेगुलेशन लागू कर दिया है।

सहकारी क्षेत्र की फर्टिलाइजर कंपनी कृभकों के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार की इस पहल से सहकारिता से जुड़ी आबादी का भला होगा। लोगों के जीवन–स्तर में सुधार होगा। देश के लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी करोड़ों महिलाओं को सहकारी आंदोलन का लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक की आपूर्ति के साथ सहकारी बैंकों से रियायती दर पर कृषि कर्ज प्राप्त होता है। समर्थन मूल्य पर उनकी उपज की सरकारी खरीद, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण करने में सहकारी संस्थाएं और कारगर साबित होंगी। यादव ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में कानूनी ढांचे की बेहद जरूरत महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी हो जाएगी।

बुनकर, मछुआरे, डेयरी क्षेत्र, हाउसिंग, श्रम, स्वास्थ्य व बीमा क्षेत्र में सहकारी संस्थायें आगे बढ़कर काम कर पाएंगी। इसका लाभ सहकारी व्यवस्था के अंतिम पायदान पर काम करने वाले सहकारी क्षेत्र में युवाओं के शिक्षण व प्रशिक्षण की सख्त जरूरत है, जो अब पूरी होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अलग मंत्रालय से, बैंकों और अन्य संबंधी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

आज लगाया पौधा सहकारिता वृक्ष के रूप में विकसित होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया पौधरोपण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर स्मार्ट पार्क में फाइकस का पौधा लगाया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर लगाया गया यह पौधा 'सहकारिता वृक्ष'के रूप में विकसित होगा। सहकारिता आंदोलन संपूर्ण प्रदेश में फले-फूले राज्य शासन इस दिशा में निरंतर सक्रिय है।

फाइकस का घर की बगिया और उद्यानों की साज-सज्जा में विशेष महत्व है। इस पौधे में हवा को साफ करने की क्षमता होती है, यह घर को ठंडा बनाए रखता है। फाइकस ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा छोड़ता है। सदाबहार पौधा होने से इसकी उम्र भी लंबी होती है।

राज्य सहकारी संघ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण

भोपाल। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल में केन्द्रीय विषय ''सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण'' पर संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी, श्री संजय सिंह द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि स्वागत से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त अपर आयुक्त एवं श्री जे.पी. गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री प्रकाश खरे, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, श्री पृथ्वीराज सिन्हा, वरिष्ठ ऐजुकेशन ऑफीसर, श्रीमति सृष्टि उमेकर कार्पोरेट ट्रेनर, श्री दिनेशचन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, श्री राघवेन्द्र सिसोदिया, अधिवक्ता, श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी एवं राज्य संघ के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पी.डी. मिश्रा द्वारा कहा गया कि इस वर्ष का ध्येय वाक्य बेहतर पुनर्निर्माण के लिए एक साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से समाज के पुनर्निर्माण को संकल्प प्रदान करना और लोगो के जीवन में उत्साह का नवीन संचार करना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सहकारजन इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में जुटे। आज विश्व जब अवसाद के दौर से गुजर रहा है ऐसे में आवश्यकता है कि हमें पूरी मानव जाति को एक परिवार मानकर एक विश्व नागरिक के रूप में पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। यह सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा कहा गया कि सहकारिता में विश्व कल्याण की भावना निहित है तथा ये विकास यात्रा में पीछे छूट गये हर व्यक्ति को साथ लेकर बढने की विचारधारा है जो एक सब से लिए, सब एक के लिए कार्य करती है। श्री प्रकाश खरे, श्रीमति सृष्टि उमेकर द्वारा भी उक्त विषय पर अपने–अपने विचार व्यक्त किये गये।

संगोष्ठी के उपरांत सभी अतिथियों द्वारा राज्य संघ परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर परिसर में 51 पौधे लगाये गये। परिसर में वृक्षारोपण के साथ यह भी संकल्प लिया गया कि आगामी दिनों में भी वृक्षारोपण लगातार जारी रखा जाएगा एवं वृक्षों की देखभाल भी नियमित तौर पर की जावेगी।

अंत में श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी संघ द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं सहकारी बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बधाई दी एवं सभी का आभार व्यक्त किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।